प्रदूषण पर रोक के लिए इलेक्ट्रिक वाहन जरूरी

मुख्य सचिव बोले- ईवी आज की जरूरत, पोर्टल किया लॉन्च

अमर उजाला ब्यूरो

प्रदेश में 1500 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने को दी गई है मंजूरी

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि शहरों में वाहनों की बढ़ती संख्या से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। लगभग 25 प्रतिशत प्रदूषण की वजह गतिशीलता है। ऐसे में प्रदेश के 17 नगर निगमों समेत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन की जरूरत है। मुख्य सचिव बुधवार को कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान पर आयोजित वर्कशॉप को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल जागरूकता पोर्टल भी लांच किया।

वर्कशाप का आयोजन प्रदेश सरकार, एशियन डेवलपमेंट बैंक और नीति आयोग ने किया था। मुख्य सचिव ने कहा कि शहर में लोग निजी वाहन से कम यात्रा करें, इसके लिए सिटी ट्रांसपोर्ट बसें चलाई जा रही हैं। 745 इलेक्ट्रिक बसें शहरों में चल रही हैं। हाल ही में 1500 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की मंजूरी दी गई है। इन बसों को एक वर्ष के भीतर लखनऊ, अयोध्या, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में चलाया जाएगा।

वाराणसी में पांच किमी रोपवे जल्द

मुख्य सचिव ने कहा कि देश में पहली बार कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए वाराणसी में पांच किमी रोपवे चलाने जा रहे हैं। बनारस से डिब्रूगढ़ तक सबसे लंबा क्रूज चलाया जा रहा है। शहरों में नदियों पर भी क्रूज चलाने पर विचार हो रहा है।

मुख्य सचिव ने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रदेश के शहरों की स्थिति बेहतर है। शहर की सड़कों को साइकिल व पैदल चलने लायक बनाया जा रहा है। कॉप-26 बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। इसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। देश में सर्वाधिक लगभग 4.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी बनाई गई। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। इन्हीं नीतियों के तहत 3.5 लाख करोड़ रुपये के एमओयू तीन महीने में दिखाई देने लगेंगे।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार अरविंद कुमार, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास नरेंद्र भूषण, प्रमुख सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू मौजूद रहे।